**International Journal of Research in Social Sciences**
Vol. 7 Issue 8, August 2017
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

# ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल विभाजन का सामाजिक असमानता पर प्रभाव

शशि प्रभा गौतम
प्रवक्ता समाजशास्त्र
शहीद मंगल पाण्डेय राजकीय महिला महाविद्यालय, बलिया।

सारांश– डिजिटल युग में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) का विस्तार सामाजिक विकास का एक महत्वपूर्ण आधार बन चुका है। तथापि, समाज के सभी वर्गों को इस तकनीकी प्रगति का समान लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप "डिजिटल विभाजन" (क्पहपजंस क्पअपकम) की समस्या उभरकर सामने आई है। प्रस्तुत शोध–पत्र का उद्देश्य ग्रामीण भारत में डिजिटल विभाजन की स्थिति तथा उसके सामाजिक असमानता पर प्रभाव का समाजशास्त्रीय विश्लेषण करना है। अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट, कंप्यूटर एवं मोबाइल सेवाओं तक पहुँच सीमित है, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तथा सूचना तक पहुँच में असमानता बढ़ती है। डिजिटल संसाधनों की असमान उपलब्धता सामाजिक स्तरीकरण को और अधिक गहरा करती है।
मुख्य शब्द– डिजिटल विभाजन, ग्रामीण भारत, सामाजिक असमानता, सूचना प्रौद्योगिकी, डिजिटल साक्षरता, विकास

प्रस्तावना– वर्तमान समय को सूचना एवं प्रौद्योगिकी का युग कहा जाता है, जहाँ डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता सामाजिक एवं आर्थिक विकास का प्रमुख आधार बन चुकी है। इंटरनेट, मोबाइल फोन तथा कंप्यूटर जैसी तकनीकों ने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार तथा शासनकृको गहराई से प्रभावित किया, किन्तु इस तकनीकी विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक समान रूप से नहीं पहुँच पाया है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल संसाधनों की सीमित उपलब्धता के कारण एक स्पष्ट "डिजिटल विभाजन" देखने को मिलता है। यह विभाजन केवल तकनीकी नहीं, बल्कि सामाजिक एवं आर्थिक असमानता का भी प्रतिबिंब है।

एनएसएसओ 2015 के अनुसार ग्रामीण भारत में केवल 15 से 20 प्रतिशत परिवारों के पास इंटरनेट या कंप्यूटर की पहुँच थी, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 40 प्रतिशत से अधिक था। आईटीयू 2015 के अनुसार भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ता कुल जनसंख्या का लगभग 26 प्रतिशत थे जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में यह अनुपात अत्यंत कम था, मोबाइल फोन की पहुँच अपेक्षाकृत अधिक थी, लेकिन स्मार्टफोन और इंटरनेट उपयोग सीमित था, जो डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता में स्पष्ट ग्रामीण–शहरी असमानता को दर्शाता है।

डिजिटल विभाजन केवल तकनीकी संसाधनों तक पहुँच का अंतर नहीं है, बल्कि यह समाज में पहले से विद्यमान वर्गीय, आर्थिक एवं सामाजिक असमानताओं को और अधिक गहरा करने वाली संरचनात्मक प्रक्रिया है। पियरे बोरदियू के सांस्कृतिक पूँजी के सिद्धांत के अनुसार, जिन वर्गों के पास पहले से ही शिक्षा, कौशल और संसाधनों की अधिकता होती है, वे नई तकनीकों को जल्दी अपनाकर और अधिक लाभ अर्जित करते हैं। इसके विपरीत, निम्न वर्ग डिजिटल संसाधनों की कमी के कारण इस लाभ से वंचित रह जाते हैं, जिससे असमानता और बढ़ती है।

भारत के संदर्भ में यह समस्या और स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। 2015 के आसपास के आंकड़ों के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुँच अत्यंत सीमित थी, जहाँ शहरी क्षेत्रों की तुलना में डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता काफी कम थी। यह अंतर केवल तकनीकी नहीं, बल्कि आर्थिक और शैक्षिक असमानताओं का प्रतिबिंब है।

अमर्त्य सेन के क्षमता दृष्टिकोण के अनुसार, विकास केवल संसाधनों की उपलब्धता से नहीं, बल्कि उन्हें उपयोग करने की क्षमता से मापा जाना चाहिए। डिजिटल विभाजन इस क्षमता को सीमित करता है, विशेष रूप से गरीब, महिलाएँ और ग्रामीण समुदाय डिजिटल शिक्षा, ई–गवर्नेंस और ऑनलाइन रोजगार के अवसरों से वंचित रह जाते हैं।

इसके अतिरिक्त, मैनुअल कास्टेल्स के नेटवर्क समाज के सिद्धांत के अनुसार, आधुनिक समाज में शक्ति और अवसर नेटवर्क्स के माध्यम से वितरित होते हैं। जो लोग इन डिजिटल नेटवर्क्स से बाहर हैं, वे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से हाशिए पर चले जाते हैं। इस प्रकार डिजिटल बहिष्करणएक नई प्रकार की सामाजिक असमानता को जन्म देता है।

आलोचनात्मक दृष्टि से देखें तो डिजिटल विभाजन केवल परिणाम नहीं, बल्कि सामाजिक संरचना का पुनरुत्पादन है। उच्च वर्ग के पास बेहतर शिक्षा, निजी उपकरण (जैसे स्मार्टफोन, लैपटॉप), और उच्च गुणवत्ता की इंटरनेट सेवाएँ होती हैं, जिससे वे डिजिटल अर्थव्यवस्था में अधिक लाभ प्राप्त करते हैं। वहीं, निम्न वर्ग सीमित संसाधनों, डिजिटल साक्षरता की कमी और अवसंरचना की समस्याओं के कारण पीछे रह जाता है।

डिजिटल विभाजन समाज में पहले से मौजूद वर्गीय असमानताओं को केवल प्रतिबिंबित ही नहीं करता, बल्कि उन्हें और अधिक गहरा एवं स्थायी बना देता है। इसलिए, इसे केवल तकनीकी समस्या के रूप में नहीं, बल्कि एक व्यापक सामाजिक–आर्थिक मुद्दे के रूप में समझने की आवश्यकता है, जिसके समाधान के लिए डिजिटल साक्षरता, सस्ती इंटरनेट सेवाएँ और समावेशी नीतियाँ अत्यंत आवश्यक हैं। डिजिटल विकास आधुनिक समाज में सामाजिक परिवर्तन का एक प्रमुख माध्यम बनकर उभरा है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के विस्तार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, शासन और आर्थिक गतिविधियों के स्वरूप को व्यापक रूप से परिवर्तित किया है। कास्टेल्स के अनुसार, डिजिटल तकनीकों ने "नेटवर्क समाज" का निर्माण किया है, जहाँ सूचना का प्रवाह और सामाजिक संबंध डिजिटल माध्यमों से संचालित होते हैं। इस प्रक्रिया ने सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा दिया है और नए अवसरों का सृजन किया है। हालाँकि, यह विकास समान रूप से वितरित नहीं है।डिजिटल पहुँच में असमानता समाज में पहले से मौजूद आर्थिक और सामाजिक विषमताओं को और अधिक गहरा करती है।

भारत में डिजिटल संसाधनों तक पहुँच (ग्रामीण, शहरी अंतर)

| सूचकांक | ग्रामीण | शहरी | |
|---|---|---|---|
| कंप्यूटर उपलब्धता | 6से 8 प्रतिशत | 28से 30 प्रतिशत | एनएसएसओ 2015 |
| इंटरनेट उपयोग | 10से 15 प्रतिशत | 40से 56 प्रतिशत | |
| मेबाइल, टेलीकॉम सदस्यता | 48 प्रतिशत | 140 प्रतिशत | ट्राई 2015 |
| ब्रॉडबैंडए इंटरनेट सदस्यता | 5 प्रतिशत से कम | 15से 20 प्रतिशत | |

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि 2015 के आसपास भारत में डिजिटल संसाधनों की पहुँच में गहरा ग्रामीण, शहरी विभाजन मौजूद था। एनएसएसओ (2015) के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में केवल लगभग 6से 8 प्रतिशत परिवारों के पास कंप्यूटर उपलब्ध था, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह आँकड़ा 30 प्रतिशत के आसपास था। इसी प्रकार, इंटरनेट उपयोग के मामले में भी ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 10 से15 प्रतिशत लोग ही इंटरनेट का उपयोग कर रहे थे, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह प्रतिशत 40 प्रतिशत से अधिक था।

दूसरी ओर, ट्राई 2015 के आँकड़े दर्शाते हैं कि टेलीकॉम सेवाओं का प्रसार भी असमान था। शहरी क्षेत्रों में टेली–डेंसिटी 140 प्रतिशत से अधिक थी (अर्थात् प्रति व्यक्ति एक से अधिक मोबाइल कनेक्शन), जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह लगभग 48 प्रतिशत ही था। ब्रॉडबैंड सेवाओं की पहुँच तो ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यंत सीमित (5 प्रतिशत से भी कम) थी, जिससे डिजिटल सेवाओं का प्रभावी उपयोग संभव नहीं हो पाता था।

आधुनिक युग को प्रायः "डिजिटल युग" कहा जाता है, जहाँ सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ने मानव जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन, व्यापार तथा सामाजिक संबंध, सभी अब डिजिटल माध्यमों से संचालित हो रहे हैं। किंतु इस प्रगति के साथ एक महत्वपूर्ण समस्या भी उभरकर सामने आई है, जिसे "डिजिटल विभाजन" कहा जाता है। यह विभाजन केवल तकनीकी संसाधनों की उपलब्धता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज में पहले से विद्यमान सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक असमानताओं को और अधिक गहरा करने वाला बहुआयामी परिकल्पना है।

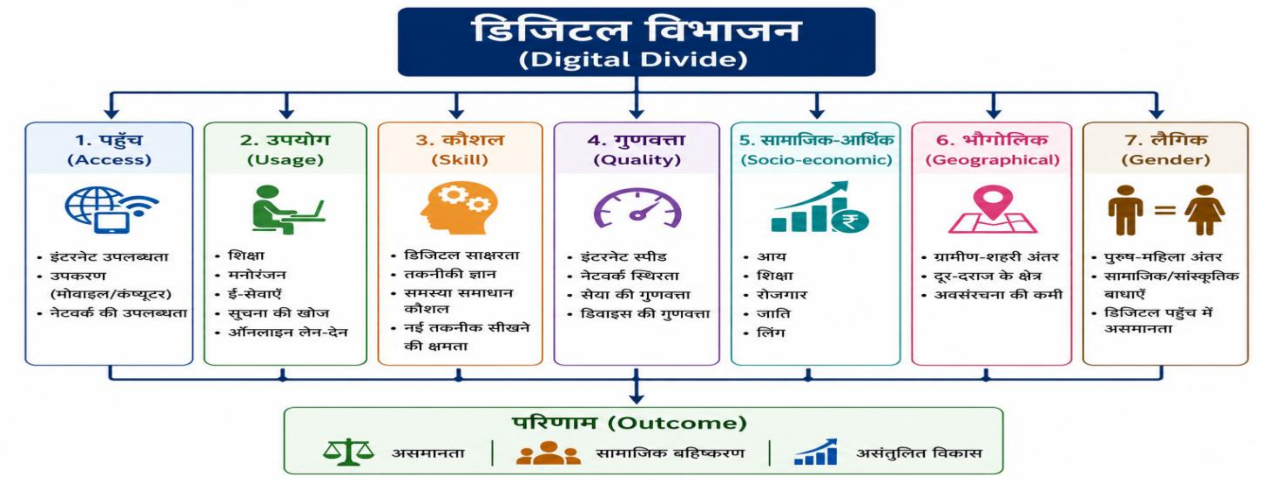


चित्र: डिजिटल विभाजन के प्रमुख आयाम

डिजिटल विभाजन का पहला और सबसे मूलभूत आयाम "पहुँच" है। समाज के सभी वर्गों के पास इंटरनेट, कंप्यूटर या स्मार्टफोन जैसी सुविधाएँ समान रूप से उपलब्ध नहीं हैं। विशेषकर ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में डिजिटल अवसंरचना की कमी के कारण लोग इन सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। इसके विपरीत, शहरी क्षेत्रों में इन संसाधनों की अधिक उपलब्धता देखने को मिलती है, जिससे एक स्पष्ट ग्रामीण–शहरी अंतर उत्पन्न होता है।

दूसरा महत्वपूर्ण आयाम "उपयोग" है। केवल डिजिटल उपकरणों का होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है, यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। समाज का एक वर्ग इंटरनेट का उपयोग शिक्षा, रोजगार और सूचना के लिए करता है, जबकि दूसरा वर्ग इसे केवल मनोरंजन तक सीमित रखता है। इस प्रकार, उपयोग के स्तर पर भी असमानता डिजिटल विभाजन को और गहरा करती है।

तीसरा आयाम "कौशल" है, जो डिजिटल साक्षरता से संबंधित है। अनेक लोग ऐसे हैं जिनके पास डिजिटल उपकरण तो उपलब्ध हैं, किंतु उन्हें प्रभावी ढंग से उपयोग करने का ज्ञान नहीं है। विशेषकर वृद्ध, कम शिक्षित तथा ग्रामीण जनसंख्या में यह समस्या अधिक दिखाई देती है। इस प्रकार, कौशल की कमी भी डिजिटल असमानता का एक प्रमुख कारण बनती है।

चौथा आयाम "गुणवत्ता" से संबंधित है। इंटरनेट की गति, नेटवर्क की स्थिरता और उपकरणों की गुणवत्ता भी सभी स्थानों पर समान नहीं होती। शहरी क्षेत्रों में उच्च गति इंटरनेट और आधुनिक उपकरण उपलब्ध होते हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में धीमा और अस्थिर नेटवर्क पाया जाता है। इससे डिजिटल सेवाओं का लाभ सीमित हो जाता है।

इसके अतिरिक्त, डिजिटल विभाजन का एक महत्वपूर्ण पहलू "सामाजिक–आर्थिक आयाम" है। आय, शिक्षा, जाति और लिंग जैसे कारक यह निर्धारित करते हैं कि कौन डिजिटल संसाधनों तक पहुँच बना सकता है और कौन नहीं। उच्च आय वर्ग के लोग बेहतर तकनीकी सुविधाएँ प्राप्त करते हैं, जबकि निम्न आय वर्ग इनसे वंचित रह जाता है। इसी प्रकार, "भौगोलिक आयाम" भी महत्वपूर्ण है, जहाँ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। दूरदराज क्षेत्रों में नेटवर्क और अवसंरचना की कमी डिजिटल पहुँच को सीमित कर देती है।

अंततः, "लैंगिक आयाम" भी डिजिटल विभाजन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। कई समाजों में महिलाओं की डिजिटल पहुँच पुरुषों की तुलना में कम होती है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाएँ इस अंतर को और बढ़ा देती हैं। इस प्रकार, डिजिटल विभाजन केवल तकनीकी नहीं, बल्कि सामाजिक असमानता का भी द्योतक बन जाता है।

इन सभी आयामों का संयुक्त प्रभाव समाज में असमानता, सामाजिक बहिष्करण और असंतुलित विकास के रूप में सामने आता है। जो लोग डिजिटल संसाधनों से वंचित रह जाते हैं, वे शिक्षा, रोजगार और सरकारी सेवाओं के अवसरों से भी दूर हो जाते हैं, जिससे वे मुख्यधारा से कट जाते हैं। डिजिटल विभाजन एक जटिल और बहुआयामी समस्या है, जिसे केवल तकनीकी समाधान से नहीं सुलझाया जा सकता। इसके लिए आवश्यक है कि सरकार और समाज मिलकर डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा दें,

सस्ती और सुलभ इंटरनेट सेवाएँ उपलब्ध कराएँ तथा समावेशी नीतियों को अपनाएँ। तभी डिजिटल विकास वास्तव में सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बन सकेगा और सभी वर्गों तक समान रूप से पहुँच पाएगा।

डिजिटल विभाजन के विभिन्न आयामों में लैंगिक डिजिटल अंतर एक अत्यंत महत्वपूर्ण और चिंताजनक पहलू है। 2014 के आसपास के आँकड़े दर्शाते हैं कि भारत में इंटरनेट उपयोग में स्पष्ट लैंगिक असमानता विद्यमान थी, जहाँ पुरुषों की भागीदारी लगभग 70: थी, जबकि महिलाओं की हिस्सेदारी मात्र 30 प्रतिशत के आसपास सीमित थी (IAMAI 2015)। यह अंतर केवल संख्यात्मक नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरे सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारण निहित हैं।

सबसे पहले, भारतीय समाज की पितृसत्तात्मक संरचना महिलाओं की डिजिटल पहुँच को सीमित करती है। अनेक परिवारों में महिलाओं को मोबाइल फोन या इंटरनेट के उपयोग की स्वतंत्रता नहीं दी जाती, या इसे अनावश्यक माना जाता है। इसके अतिरिक्त, महिलाओं की शिक्षा का निम्न स्तर भी एक प्रमुख कारण है, क्योंकि डिजिटल तकनीकों का प्रभावी उपयोग करने के लिए बुनियादी साक्षरता और तकनीकी ज्ञान आवश्यक होता है। आर्थिक दृष्टि से भी महिलाएँ अक्सर निर्भर स्थिति में होती हैं, जिसके कारण वे डिजिटल उपकरण जैसे स्मार्टफोन या कंप्यूटर, खरीदने में सक्षम नहीं होतीं। यही कारण है कि डिजिटल संसाधनों तक पहुँच में पुरुषों की तुलना में महिलाएँ पीछे रह जाती हैं। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में यह अंतर और अधिक स्पष्ट हो जाता है, जहाँ सामाजिक मान्यताएँ और संसाधनों की कमी दोनों ही महिलाओं के डिजिटल उपयोग को सीमित करते हैं।

इस लैंगिक डिजिटल अंतर का प्रभाव केवल व्यक्तिगत स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यापक सामाजिक विकास को भी प्रभावित करता है। जब महिलाएँ डिजिटल संसाधनों से वंचित रहती हैं, तो वे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, ई–गवर्नेंस और ऑनलाइन रोजगार के अवसरों से भी दूर हो जाती हैं। इससे उनकी सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की प्रक्रिया बाधित होती है और लैंगिक असमानता और गहरी हो जाती है। आलोचनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो यह अंतर केवल "तकनीकी पहुँच" की समस्या नहीं है, बल्कि यह सामाजिक बहिष्करण का एक रूप है। डिजिटल युग में सूचना और अवसरों का प्रमुख स्रोत इंटरनेट बन चुका है, और जब समाज का एक बड़ा वर्ग, विशेषकर महिलाएँ इससे वंचित रह जाता है, तो विकास की प्रक्रिया असंतुलित हो जाती है। डिजिटल विभाजन का लैंगिक आयाम अत्यंत गहरा है। अतः आवश्यक है कि नीतिगत स्तर पर महिलाओं की डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा दिया जाए, उन्हें सस्ती और सुलभ तकनीकी सुविधाएँ प्रदान की जाएँ, तथा सामाजिक स्तर पर जागरूकता बढ़ाई जाए, ताकि यह लैंगिक अंतर कम किया जा सके और डिजिटल विकास वास्तव में समावेशी बन सके।

## निष्कर्ष–

डिजिटल विभाजन को कम करने के लिए केवल तकनीकी विकास पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसके लिए समावेशी और लक्षित नीतिगत हस्तक्षेपों की आवश्यकता होती है। इस संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल अवसंरचना का विस्तार अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी उच्च गति इंटरनेट और विश्वसनीय नेटवर्क की कमी पाई जाती है, जिसके कारण वहाँ के लोग डिजिटल सेवाओं का पूर्ण लाभ नहीं उठा पाते। अतः सरकार और निजी क्षेत्र को मिलकर दूरदराज क्षेत्रों तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और मोबाइल नेटवर्क का विस्तार करना चाहिए। इसके साथ ही, डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों का व्यापक स्तर पर संचालन आवश्यक है। केवल इंटरनेट उपलब्ध कराना पर्याप्त नहीं है, बल्कि लोगों को यह भी सिखाना जरूरी है कि वे डिजिटल तकनीकों का उपयोग कैसे करें। विशेष रूप से ग्रामीण जनता, वृद्ध व्यक्तियों और कम शिक्षित वर्गों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए, ताकि वे डिजिटल सेवाओं का प्रभावी उपयोग कर सकें।

सस्ती इंटरनेट सेवाएँ भी डिजिटल समावेशन के लिए एक महत्वपूर्ण कारक हैं। यदि इंटरनेट सेवाएँ महँगी होंगी, तो निम्न आय वर्ग के लोग इनका उपयोग नहीं कर पाएँगे। इसलिए, डेटा प्लान्स को किफायती बनाना और सार्वजनिक स्थानों पर मुफ्त या सस्ती इंटरनेट सुविधाएँ उपलब्ध कराना आवश्यक है। अंततः, महिलाओं और कमजोर वर्गों पर विशेष ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। समाज के ये वर्ग अक्सर डिजिटल संसाधनों से वंचित रह जाते हैं। महिलाओं के लिए विशेष डिजिटल प्रशिक्षण कार्यक्रम, स्व–सहायता समूहों के माध्यम से जागरूकता अभियान तथा सामाजिक बाधाओं को कम करने के

प्रयास किए जाने चाहिए। इसी प्रकार, अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के लिए भी लक्षित योजनाएँ बनाई जानी चाहिए। डिजिटल विभाजन को समाप्त करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है, जिसमें अवसंरचना, शिक्षा, आर्थिक सुलभता और सामाजिक समावेशन सभी को समान महत्व दिया जाए। तभी डिजिटल विकास वास्तव में समावेशी और संतुलित बन सकेगा।

संदर्भ सूची–


1. Bourdieu, P. (1986). *The forms of capital*. In J. Richardson (Ed.), Handbook of theory and research for the sociology of education (pp. 241–258). Greenwood Press.
2. Castells, M. (2000). *The rise of the network society* (2nd ed.). Blackwell Publishers.
3. Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.
4. Van Dijk, J. (2005). *The deepening divide: Inequality in the information society*. Sage Publications.
5. Norris, P. (2001). *Digital divide: Civic engagement, information poverty, and the Internet worldwide*. Cambridge University Press.
6. DiMaggio, P., & Hargittai, E. (2001). From the 'digital divide' to 'digital inequality': Studying Internet use as penetration increases. *Princeton University Center for Arts and Cultural Policy Studies*, Working Paper Series.
7. Helsper, E. J. (2012). A corresponding fields model for the links between social and digital exclusion. *Communication Theory, 22*(4), 403–426.
8. NSSO. (2015). *Key indicators of social consumption in India: Education (NSS 71st Round)*. National Sample Survey Office, Government of India.
9. Telecom Regulatory Authority of India (TRAI). (2015). *The Indian telecom services performance indicators*. Government of India.
10. World Bank. (2016). *World development report 2016: Digital dividends*. World Bank.
11. Ministry of Electronics and Information Technology. (2015). *Digital India Programme: Policy document*. Government of India.
12. ITU (International Telecommunication Union). (2015). *Measuring the information society report*. ITU Publications.
13. OECD. (2011). *Divided we stand: Why inequality keeps rising*. OECD Publishing.
14. UNDP. (2015). *Human development report 2015: Work for human development*. United Nations Development Programme.
15. Warschauer, M. (2003). *Technology and social inclusion: Rethinking the digital divide*. MIT Press.
16. James, J. (2008). *Digital divide across all citizens of the world: A new concept*. *Social Indicators Research, 89*(2), 275–282.